web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

Social Justice Union — Govt. Registered

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, सोमवार 14 फरवरी 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 138

महत्वपूर्ण एवं खास

अज्ञात वाहन की टक्कर से दो लोगों की मौत

जालौन/उरई (आरएनएस)। उत्तरप्रदेश के उरई में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक व युवती घायल हुए। अस्पताल लाते समय युवक की मौत हुई। वहीं, इलाज के दौरान युवती ने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के दतिया जिला क्षेत्र के सगतपुरा निवासी किसान मुलायम सिंह के पुत्र जितेंद्र कुमार सिंह (18) शनिवार को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अम्मरगढ़ में अपने मामा के यहां आया था। शनिवार की दोपहर में वह मामा की बेटी आकांक्षा (18) पुत्री लालबहादुर के साथ जालौन बाजार में सामान की खरीदारी के लिए बाइक से आया था। देर शाम करीब साढ़े 7 बजे बाजार से सामान की खरीददारी कर वह वापस गांव लौट रहा था। तभी कोंच रोड पर लहचूरा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक युवती सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी लाया गया। जहां अस्पताल पहुंचने से पहले जितेंद्र की मौत हो गई। उधर, गंभीर रूप से घायल आकांक्षा को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। लेकिन इलाज के दौरान देर रात आकांक्षा ने भी दम तोड़ दिया। जब उनकी मौत की खबर परिजनों को मिली तो दोनों ही परिवारों में गम छा गया। एक्सीडेंट में भांजे और बेटी की मौत से लालबहादुर के साथ ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रैला अमोलो ओडिंगा के बीच हुई बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रैला अमोलो ओडिंगा, जो इस समय भारत में निजी यात्रा पर हैं, के साथ भेंट की। दोनों नेताओं के दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिंगा से लगभग साढ़े तीन वर्षों के बाद मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने 2008 से ओडिंगा के साथ भारत और केन्या, दोनों देशों में हुई कई बातचीत के साथ-साथ 2009 और 2012 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए उनके समर्थन को याद किया। दोनों राजनेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत-केन्या संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिंगा को उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।

अटलांटिक महासागर में जहाज से गायब हुआ केरल का युवक, परिवार ने विदेश मंत्रालय से मांगी मदद

नई दिल्ली (आरएनएस)। अटलांटिक महासागर में एक जहाज से केरल का एक युवक लापता हो गया। युवक के परिवार ने उसे खोजने के लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है। 28 वर्षीय युवक एक जहाज पर सहायक रसोइया के रूप में काम कर रहा था। जस्टिन कुरुविला के रूप में पहचाने गए युवक ने 31 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका (डरबन) से अमेरिका के लिए अपनी यात्रा शुरू की। युवक की बहन शिघा ने कहा, जहाज 31 जनवरी को डरबन से शुरू हुआ था। वह हमें हर दिन फोन करता था, लेकिन आखिरी कॉल एक हफ्ते पहले थी। उस दिन के बाद, उसने हमारी कॉल का जवाब देना बंद कर दिया।

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एमपीएफ की वृहद् योजना को जारी रखने की दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की वृहद् (अम्ब्रेला) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस अनुमोदन से,2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और कामकाज में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को जारी रखने की मंजूरी मिली है। 26,275 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ, इस योजना में सभी प्रासंगिक उप-योजनाएं शामिल हैं, जो आधुनिकीकरण और सुधार में योगदान करती हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

1) योजना के तहत ; आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता और देश में एक मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के प्रावधान किये गए हैं।

2) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए केंद्रीय परिव्यय के रूप में 4,846 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं।

3) संसाधनों के आधुनिकीकरण के माध्यम से विज्ञान-आधारित और समय पर जांच में सहायता के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं का विकास करना, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित हों। फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 2,080.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना को मंजूरी दी गई है।

4) केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 18,839 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

5) वामपंथी उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के कार्यान्वयन से, एलडब्ल्यूई हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है। इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने के लिए, 8,689 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ एलडब्ल्यूई से संबंधित छह योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बेहतर स्थिति को और मजबूती देने के लिए इन योजनाओं में अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और अन्य सम्बंधित जिलों की विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) को शामिल किया गया है।

6) भारतीय रिजर्व बटालियनों/विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

7) 50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना,मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता को जारी रखा गया है।

करोड़ों की अवैध शराब व ड्रग्स जब्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी

लखनऊ (आरएनएस)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 99,88,993 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 74,92,435 एवं निजी स्थानों से 24,96,558 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी और कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स और अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक 8,71,447 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये, जिसमें से आज 3092 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये। अब तक 628 लाइसेन्स जब्त किए गए तथा 1863 लाइसेन्स निरस्त किये गये। निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये 31,94,875 लोगों को पाबन्द किया गया हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक विभिन्न धाराओं में 1317 एफआईआर दर्ज करायी गयी है, जिसमें से आज विभिन्न धाराओं में 55 एफआईआर दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अब तक 8966 शस्त्र, 9337 कारतूस, 229 विस्फोटक एवं 280 बम बरामद किये गये। पुलिस विभाग द्वारा रेड डालकर अवैध शस्त्र बनाने वाली 172 फैक्ट्रियों को सीज किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग एवं आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 75.55 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 42 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 15,16,645 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं।

नर्मदा घाटी परियोजना की टनल में बड़ा हादसा, मिट्टी में 9 लोग दबे, रेस्क्यू जारी

कटनी (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बीती शाम बड़ा हादसा हो गया. यहां के स्लीमनाबाद में नर्मदा घाटी परियोजना की टनल की मिट्टी धंस गई। मिली जानकारी के अनुसार सुरंग में कुल 9 मजदूर धस्स गए। सुरंग के धंसने के बाद मलबे में फंसे 9 मजदूर में से 5 को बचा लिया गया। जबकि स्ष्ठक्रस्न की टीम द्वारा बचाव अभियान अभी भी जारी है। राजधानी भोपाल से इस पूरे मामले की गृह विभाग लाइव मॉनिटरिंग कर रहा है। खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पल-पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। इस मामले में जांच कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी के स्लीमनाबाद में हुई घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने कटनी कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर घटना की जानकारी ली। वह निरंतर कटनी जिला प्रशासन से संपर्क में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं।

ये हादसा बरगी के दायें तट पर नहर के लिए बनाई जा रही अंडरग्राउंड टनल के निर्माण के दौरान शनिवार शाम करीब 7.30 बजे हुआ। टनल की मिट्टी धंस गई और उसमें 9 मजदूर दब गए। इनमें से 3 मजदूरों को तो उसी वक्त सुरक्षित निकाल लिया गया था। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है।

महंगाई कम करनी है तो भाजपा को हराना होगा, भूपेश बघेल ने किया रोड शो

0- बोले,जीएसटी से अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय हो गई चौपट

कानपुर (आरएनएस)। उत्तरप्रदेश के कानपुर में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। महंगाई कम करना चाहते हैं और रोजगार चाहते हैं तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की बात पर विश्वास करना होगा। वह रविवार को कानपुर में गोविंद नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि देश दुनिया में औधोगिक नगरी के नाम से पहचान रखने वाला और लाखों लोगों को रोजगार देने वाले कानपुर अब भाजपा की सरकार में चौपट हो गया है। यहां भी रोजी-रोटी, महंगाई की समस्या पैदा हो गई है। उपचुनाव हुए हिमांचल प्रदेश में, एक लोक और तीन विधानसभा में क्षेत्र में और भाजपा तीनों में हार गई थी। इसके बाद पेट्रोल में पांच और डीजल में दस रुपये कम हुए थे। महंगाई कम करनी है तो भाजपा को हराना होगा। रोजगार चाहिए तो प्रियंका वाड्रा की बात पर विश्वास करना होगा। उन्होंने 20 लाख नौकरी देने का वादा किया है, कांग्रेस जो कहती है करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा राहुल गांधी ने कहा था तो छत्तीसगढ़ में आज भी 2500 रुपये कुंतल में धान बिक रहा है। वहां गोबर तक खरीदा जा रहा है।

गोविंदनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो काली मठिया से शुरू हुआ शास्त्री नगर होता हुआ विजय नगर चौराहा पहुंचा और जनसभा में तब्दील हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चौराहा पर पूर्व पार्षद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगनारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने शास्त्री नगर कालोनी के मालिकाना हक की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को बसाने की बात करती है। पट्टा चाहिए तो कांग्रेस का साथ दीजिए। मोदी जी नेहरू इंदिरा से सवाल करते हैं, जब वह प्रधानमंत्री बने थे तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने जो किया वह इतिहास में दर्ज है। मैं सवाल करता हूं कि नोटबंदी से काला धन वापस आया, इसका जवाब दें। उन्होंने कहा था जीएसटी से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी लेकिन वह चौपट हो गई। आप बाद में सवाल करना, कोरोना काल मे गंगा में कितनी लाशें बहीं पहले इसके बारे में बताएं। यहां से उनका काफिला किदवई नगर में रोड शो के लिए निकल गया।

17वां एमआईएफएफ 29 मई से 4 जून, तक आयोजित किया जाएगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और विदेशों में फिल्म निर्माताओं एवं सिनेमाघरों द्वारा बहुप्रतीक्षित, वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफएफ-2022) 29 मई से 4 जून, 2022 तक फिल्म डिवीजन परिसर, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। प्रविष्टियों की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से 15 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक खुली रहेगी 1 सितंबर, 2019 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच निर्मित फिल्में एमआईएफएफ-2022 में प्रविष्टि की पात्र हैं। समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र को स्वर्ण शंख और 10 लाख रुपये नकद पुरस्कार मिलेगा। विभिन्न श्रेणियों में विजेता फिल्मों को आकर्षक नकद पुरस्कार, रजत शंख, ट्राफियां और प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। भारत के आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर, वर्तमान आयोजन में भारतञ्च75 विषय पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए एक विशेष पुरस्कार की स्थापना की गई है। इस समारोह में भारतीय गैर-फीचर फिल्म श्रेणी के एक अनुभवी व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपये नकद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र सौंप कर सम्मानित किया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीजन द्वारा आयोजित और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समर्थित दक्षिण एशिया में गैर-फीचर फिल्मों के लिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा समारोह- एमआईएफएफ, दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रतियोगिता और गैर-प्रतिस्पर्धा वर्गों के अलावा, कार्यशालाओं, मास्टर कक्षाओं, ओपन फोरम और बी 2 बी सत्र जैसे इंटरैक्टिव सत्र इस समारोह के प्रमुख आकर्षण हैं।

2020 में आयोजित 16वें द्विवार्षिक एमआईएफएफ के प्रति गहरी रुचि दिखाई गई थी, जो भारत और दुनिया में एक जीवंत वृत्तचित्र संस्कृति को दर्शाता है। 16वें एमआईएफएफ को भारत और विदेशों से अभूतपूर्व 871 प्रविष्टियां प्राप्त हुई और इसमें भारत व दुनिया के अन्य हिस्सों के कई प्रमुख वृत्तचित्र, एनिमेशन और लघु फिल्म निर्माताओं ने भाग लिया। ग्रैंड जूरी में फ्रांस, जापान, सिंगापुर, कनाडा, बुल्गारिया और भारत की प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियां शामिल थीं।

राष्ट्र्व्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 172.81 करोड़ से अधिक लगे टीके

नई दिल्ली (आरएनएस)। 24 घंटों में 49.16 लाख से अधिक (49,16,801) वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 172.81 करोड़ (1,72,81,49,447) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,93,53,556 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है। 24 घंटों में 49.16 लाख से अधिक (49,16,801) वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 172.81 करोड़ (1,72,81,49,447) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,93,53,556 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है। पिछले 24 घंटे में 44,877 नए मरीज सामने आए हैं। वर्तमान में 5,37,045 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 1.26 प्रतिशत हैं। देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,15,279 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 75.07 करोड़ (75,07,35,858) जांच की गई हैं।

देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.46 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.17 प्रतिशत है।

तीसरी तिमाही के दौरान मॉयल के शुद्ध लाभ में 305 प्रतिशत की वृद्धि हुई

नई दिल्ली (आरएनएस)। मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल), जो इस्पात मंत्रालय के अधीनस्थ अनुसूची 'ए' सीपीएसई है, का शुद्ध लाभ 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त नौ महीनों में 305 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 245.91 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 60.59 करोड़ रुपये था। मॉयल लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई।

इस बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए 30 प्रतिशत (अर्थात 3.00 रुपये प्रति शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश देने की भी सिफारिश की। कंपनी ने पिछले साल 2.50 रुपये प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश दिया था।

कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर का प्रतिकूल प्रभाव कंपनी की परिचालन गतिविधियों पर पडऩे के बावजूद मॉयल बेहतर उत्पादन योजना और विपणन रणनीति की बदौलत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम रही है। उपर्युक्त नौ माह की अवधि के दौरान कंपनी ने अपने परिचालन से 968.41 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 727.26 करोड़ रुपये था। कंपनी ने अपने उत्पादन में भी 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है क्योंकि उपर्युक्त अवधि के दौरान मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 7.41 लाख टन से बढक़र 8.57 लाख टन हो गया।

कंपनी ने पिछले चार वित्त वर्षों में तीसरी तिमाही के दौरान सर्वाधिक कारोबार और कुल आय अर्जित की है। कंपनी द्वारा अर्जित किया गया 123.88 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक का सर्वाधिक तिमाही मुनाफा है।

हिजाब विवाद : कर्नाटक में कल से खुलेंगे हाईस्कूल, सीएम बोम्मई ने जताया शांति का भरोसा

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक के उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था। यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक लागू रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था। आदेश के अनुसार, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

हाईस्कूलों के फिर से खुलने पर बोम्मई ने शांति बहाल होने का विश्वास जताया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्यभर में 10वीं कक्षा तक के हाईस्कूलों के फिर से खुलने से एक दिन पहले रविवार को विश्वास जताया कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी। राज्य में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के कारण इन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। बोम्मई ने कहा कि प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, 10वीं कक्षा तक के हाईस्कूल कल फिर से खुलेंगे, सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सार्वजनिक निर्देश के उपनिदेशक को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्कूलों में अभिभावकों और शिक्षकों की शांति बैठकें बुलाने के लिए कहा गया है। मुझे विश्वास है कि स्कूलों में शांतिपूर्ण तरीके से काम होगा। उन्होंने प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के बाद शिक्षा मंत्री से एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसके आधार पर एक बैठक की जाएगी और फैसला लिया जाएगा।